

## हरियाणा जिले में कृषि पर COVID 19 का प्रभाव

ममता

टीजीटी इंग्लिश

सार

आधिकारिक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत COVID-19 के प्रकोप के खिलाफ तैयारी कर रहा है, और विशिष्ट संकट कार्यों से बचने या इसके महत्व को न समझने के अत्यंत गंभीर परिणाम होंगे। भारत के सभी पड़ोसी देशों ने सकारात्मक COVID-19 मामलों की सूचना दी है। घातक वायरस से बचाव के लिए, भारत सरकार ने आवश्यक और सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं के बीच स्वास्थ्य जांच चौकियां स्थापित करना शामिल है, ताकि यह जांचा जा सके कि देश में प्रवेश करने वाले लोगों में वायरस है या नहीं। विभिन्न देशों ने चीन से लौटने के इच्छुक नागरिकों के लिए बचाव के प्रयास और निगरानी के उपाय शुरू किए हैं। सार्स के प्रकोप से पहला सबक यह मिला कि सार्स के बारे में स्पष्टता और जानकारी की कमी ने चीन की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर दिया और उसके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की। चीन में सार्स का प्रकोप विनाशकारी था और इससे स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा प्रणालियों में बदलाव आया है। चीन की तुलना में भारत की महामारी का मुकाबला करने की क्षमता काफी कम नजर आ रही है। हाल के एक अध्ययन में बताया गया है कि प्रभावित परिवार के सदस्य चीन के वुहान बाजार में नहीं गए थे, यह सुझाव देते हुए कि SARS-CoV-2 लक्षण प्रकट किए बिना फैल सकता है।

शोधकर्ताओं का मानना है कि कई वायरस के लिए यह घटना सामान्य है। भारत, जिसकी आबादी 1.34 बिलियन से अधिक है – दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है – को गंभीर COVID-19 मामलों का इलाज करने में कठिनाई होगी क्योंकि देश में केवल 49,000 वेंटिलेटर हैं, जो कि एक न्यूनतम राशि है। यदि देश में COVID-19 मामलों की संख्या बढ़ती है, तो यह भारत के लिए एक आपदा होगी। संक्रमण के स्रोत और उनके संपर्क में आने वालों की पहचान करना मुश्किल होगा। नए टीकों और दवा उपचारों को तेजी से विकसित करने के लिए कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग के साथ-साथ सांख्यिकीय और मात्रात्मक विश्लेषण सहित प्रकोप को संभालने के लिए कई रणनीतियों की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी आबादी के साथ, भारत की चिकित्सा प्रणाली घोर अपर्याप्त है। एक अध्ययन से पता चला है कि अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रणाली के कारण, भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत अपने आस-पास के देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन और नेपाल के साथ व्यापार में भी लगा हुआ है।

## भूमिका

वित्तीय वर्ष 2017-18 (FY2017-18) के दौरान, भारतीय क्षेत्रीय व्यापार लगभग +12 बिलियन का था, जो इसके कुल वैश्विक व्यापार मूल्य +769 बिलियन का केवल 1.56% है। ऐसे वायरस का प्रकोप और उनका संचरण भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। चीन में प्रकोप का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक्स संचालन के क्षेत्रों में, क्योंकि चीन के साथ व्यापार बंदरगाह वर्तमान में बंद हैं। इसे सुयश चौधरी, हेड-फिक्स्ड इनकम, आईडीएफसी एएमसी के बयान से और समर्थन मिला, जिसमें कहा गया था कि सीओवीआईडी-19 के कारण जीडीपी में कमी आ सकती है।

अर्थशास्त्री मानते हैं कि 2003 के दौरान SARS के प्रभाव की तुलना में अर्थव्यवस्था पर बट्टक-19 का प्रभाव उच्च और नकारात्मक होगा। उदाहरण के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि चीन में आने वाले पर्यटकों की संख्या यात्रा करने वाले पर्यटकों की तुलना में बहुत अधिक थी। मौसम के दौरान जब सार्स 2003 में उभरा। इससे पता चलता है कि COVID-19 का पर्यटन उद्योग पर प्रभाव है। यह अनुमान लगाया गया है कि, सार्स के लिए, वार्षिक रेल यात्री और सड़क यात्री यातायात में क्रमशः 57 और 45% की गिरावट आई थी। इसके अलावा, जब 15 साल पहले विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तुलना की जाती है, तो विश्व अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में बहुत अधिक परस्पर जुड़ी हुई हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि COVID-19 उभरती बाजार मुद्राओं को नुकसान पहुंचाएगा और तेल की कीमतों को भी प्रभावित करेगा।

खुदरा उद्योग के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता बचत अधिक प्रतीत होते हैं। इसका उपभोग दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रभावित होने की संभावना है, जो बदले में विभिन्न आवश्यक उत्पाद वस्तुओं की मांग की तुलना में आपूर्ति पर इसका प्रभाव डालेगा। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि, पर्यटन पर SARS के प्रभाव के कारण अनुमानित नुकसान के आधार पर (खुदरा बिक्री में लगभग 12-18 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान हुआ और वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक स्तर पर 30-100 बिलियन अमरीकी डालर का नुकसान हुआ), हम COVID के प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। -19 इस बिंदु पर। यह तभी संभव होगा जब COVID-19 के प्रसार को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाएगा। उस समय तक, कोई भी अनुमान अस्पष्ट और सटीक होगा। ओईसीडी अंतरिम आर्थिक मूल्यांकन ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और कमोडिटी बाजारों में चीन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ब्रीफिंग रिपोर्ट प्रदान की है।

जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो प्रतिकूल प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील हैं, क्योंकि उनके चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कारों की बिक्री में 20% की गिरावट आई है, जो जनवरी 2020 के दौरान चीन में मासिक गिरावट का 10% थी। इससे पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन भी COVID-19 से प्रभावित हुआ है। अब तक, कई कारकों को एक प्रमुख आर्थिक प्रभाव के रूप में पहचाना गया है—श्रम गतिशीलता, काम के घंटों की कमी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट, कम खपत और पर्यटन, और वैश्विक स्तर पर कमोडिटी बाजार में कम मांग, जो बदले में उद्योग प्रकार द्वारा पर्याप्त रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट नेताओं को उपभोक्ता की ओर से मांग के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला और उत्पाद लाइन अर्थव्यवस्था के रुझान को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। COVID-19 प्रभाव से पहले स्थायी अर्थव्यवस्था पर कई बहसों के बीच, अब यह अनुमान लगाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 2011 के लिए 5.8% से घटाकर 1.9% कर दिया गया है। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण जो वित्तीय संकट सामने आया है, वह कई उद्योगों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020 के लिए सकल घरेलू उत्पाद गिरकर 4.2% हो गया है, जो पहले 4.8% अनुमानित था। फिर भी, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि भारत और चीन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच काफी सकारात्मक विकास का अनुभव करेंगे।

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले दो साल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहे हैं। संक्रमण की नयी लहरों, आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान, और हाल ही में मुद्रास्फीति के कारणवश नीति-निर्माण के लिए यह समय विशेषतः चुनौतीपूर्ण रहा है। इन चुनौतियों की तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं व्यापार क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सुरक्षा-जाल का गठन किया। इसके उपरांत, बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी, ताकि मध्यम-अवधि की मांग पुनः बढ़े, एवं अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति-पक्ष उपायों को कृतसंकल्प लागू किया गया। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे यह लचीला और बहुस्तरीय दृष्टिकोण आंशिक रूप से "एजाइल" (चुस्तदुरुस्त) कार्यप्रणाली पर आधारित है जो फीडबैक-लूप (प्रतिक्रिया-पाश) और रीयल-टाइम डेटा (वास्तविक-काल आंकड़ों) का उपयोग करती है।

## हरियाणा जिले में कृषि पर COVID 19 का प्रभाव

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 में 7.3 प्रतिशत संकुचन के बाद, अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 में 9.2 प्रतिशत के विस्तार की उम्मीद है। कुल मिलाकर, आर्थिक गतिविधि पूर्व-महामारी/2019-20 के स्तर से उभर चुकी है। लगभग सभी संकेतकों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की षूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव पहली लहर के दौरान पूर्ण-लॉकडाउन चरण की तुलना में बहुत कम था, यद्यपि स्वास्थ्य प्रभाव अधिक गंभीर था। महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं और पिछले वर्ष में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। 2020-21 में 7 प्रतिशत संकुचन के पश्चात्, उद्योग के सकल मूल्य वर्धन (खनन और निर्माण सहित) में 2021-22 में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि अग्रिम तौर पर अनुमानित है। सेवा क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से ऐसे खंड जिनमें मानव संपर्क शामिल हैं। पिछले साल के 8.4 फीसदी के संकुचन के बाद इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के 8.2 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

2021-22 में कुल खपत में 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी खर्च का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल अचल पूंजी निर्माण के महामारी पूर्व के स्तर से अधिक होने में भी बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का योगदान है। वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में असाधारण रूप से मजबूत रहा है, वहीं घरेलू मांग और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते आयात में भी मजबूती आई है। टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी के शामिल होने, आर्थिक गति तीव्र होने, और आपूर्ति-पक्ष सुधारों के संभावित दीर्घकालिक लाभों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.0-8.5 प्रतिशत की वृद्धि देखने की अच्छी स्थिति में है। बहरहाल, वैश्विक वातावरण अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। लेखन के समय ओमिक्रोन संक्रमण के रूप में एक नई लहर दुनिया भर में फैल रही थी, अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई थी, और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक तरलता निकासी का दौर शुरू किया जा रहा था। इसलिए, भारत के वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतकों और उनकी उपरोक्त दबावों के विरुद्ध समर्थन प्रदान करने की क्षमता को जांचना विशेषतः महत्वपूर्ण है।

वैश्विक महामारी के कारण हुए सभी व्यवधानों के बावजूद, पिछले दो वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष में रहा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार जमा होता रहा, और 31 दिसंबर 2021 को यह 634 बिलियन डॉलर था। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है और देश के विदेशी ऋण से अधिक है। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बढ़ती निर्यात

आय का संयोजन 2022–23 में संभावित वैश्विक मौद्रिक तरलता के प्रतिगमन के विरुद्ध उपयुक्त प्रतिरोधक प्रदान करेगा। अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में हुए व्यय के कारण 2020–21 में राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में वृद्धि हुई। हालांकि, 2021–22 में सरकारो राजस्व में एक मजबूत पलटाव हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार वित्तीय समर्थन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि को कायम रखते हुए इस वर्ष के अपने वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से पूरा करने में सक्षम है। राजस्व में प्रबल पुनः प्रवर्तन (अप्रैल–नवंबर 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 67 प्रतिशत की वृद्धि थी) का अभिप्राय है कि आवश्यकता की स्थिति में सरकार के पास अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय गुंजाइश है। अनिश्चित समय के दौरान वित्तीय तंत्र दबाव का एक संभावित क्षेत्र होता है। हालांकि, भारत के पूंजी बाजारों ने कई वैश्विक बाजारों की तरह असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी मदद से भारतीय कंपनियों के लिए रिकॉर्ड- स्तर पर जोखिम पूंजी जुटाना संभव हुआ है। गौरतलब है की बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से पूंजीकृत है और गैर-निष्पादित आस्तियों में, महामारी के विलम्बित प्रभाव को मिलाकर भी, संरचनात्मक रूप से गिरावट आई है।

टीकाकरण केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर संपर्क-गहन सेवाओं के लिए। इसलिए, इसे अभी के लिए एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान के एक वर्ष में भारत ने 157 करोड़ खुराक दी हैं, जिसमें 91 करोड़ लोगों को कम-से-कम एक खुराक और 66 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गयी हैं। लेखन के समय, बूस्टर और 15–18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीकाकरण प्रक्रिया भी गति पकड़ रही थी। उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एक वैश्विक मुद्दे के रूप में फिर से सामने आई है। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.6 प्रतिशत वर्ष-पर-वर्ष थी जो कि लक्षित सीमा के भीतर है। हालांकि, थोक मूल्य मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में चल रही है। यद्यपि यह आंशिक रूप से अल्पकालिक आधार प्रभावों के कारण है, भारत को आयातित मुद्रास्फीति से सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से।

कुल मिलाकर, वृहद-आर्थिक स्थिरता संकेतक बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022–23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छी स्थिति में होने का एक कारण इसकी अनूठी प्रतिक्रिया रणनीति है। कठोर प्रतिक्रिया के लिए पूर्व-प्रतिबद्ध होने के बजाय, भारत सरकार ने एक ओर कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा-जाल का उपयोग करने का विकल्प चुना, जबकि सूचना की "बेजियन-अपडेटिंग" के आधार पर पुनरावृत्त रूप से प्रतिक्रिया दी। पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में इस बारबेल रणनीति पर चर्चा की गई थी। इस लचीले,

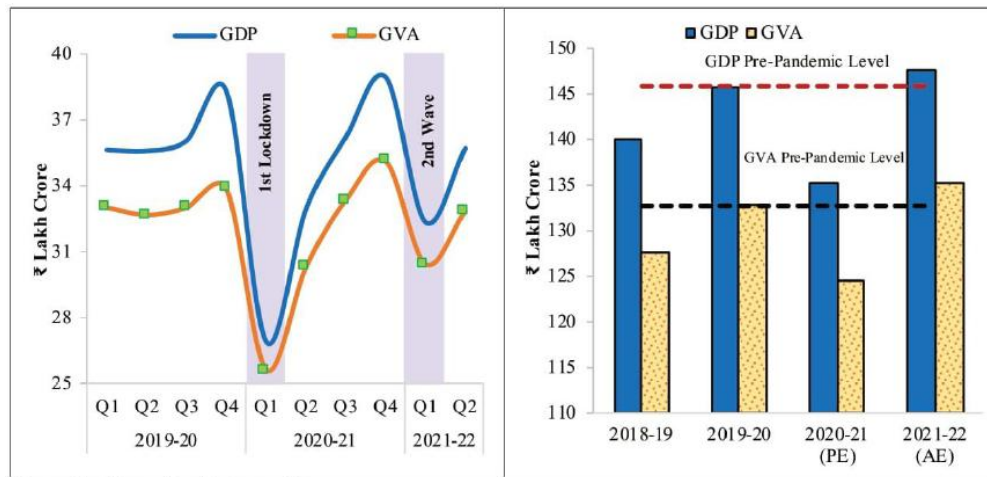
पुनरावृत्त "एजाइल" कार्यप्रणाली का एक प्रमुख प्रवर्तक 80 उच्च-आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) का उपयोग और अत्यधिक अनिश्चितता के वातावरण में संकेतों से प्रसार को अलग करने की कला है। भारत की प्रतिक्रिया की एक और विशिष्ट विशेषता मांग-प्रबंधन पर पूर्ण निर्भरता के बजाय आपूर्ति-पक्ष सुधारों पर जोर देना है। इन आपूर्ति-पक्ष सुधारों में कई क्षेत्रों का अविनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, श्रवणव्यापी कर जैसे पुराने मुद्दों का निराकरण, निजीकरण, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इन पर संबंधित अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि को मांग-प्रबंधन के साथ-साथ आपूर्ति-पक्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह भविष्य के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता का निर्माण करती है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा प्रक्रिया सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालती है एवं आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए उपग्रह छवियों और भू-स्थानिक डेटा – जो नूतन अविनियंत्रित क्षेत्रों में से एक हैं – के उपयोग का एक संक्षिप्त प्रदर्शन प्रदान करता है।

कोविड-19 महामारी के दो साल के दौरान पुनरुत्थान लहरों, आपूर्ति-शृंखला व्यवधानों और उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की वापसी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता से त्रस्त रही है। इसके अलावा, अगले वर्ष के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि की संभावित वापसी से भी वैश्विक पूंजी प्रवाह अधिक अस्थिर हो सकता है। इस संदर्भ में, भारत में विकास पुनरुद्धार की गति के साथ-साथ व्यापक-आर्थिक स्थिरता संकेतकों की ताकत दोनों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में प्रगति को देखना भी आवश्यक है क्योंकि यह न केवल एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया है, बल्कि बार-बार महामारी की लहरों के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के खिलाफ एक प्रतिरोधक भी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों में देखा गया है, 2020-21 की दूसरी छमाही से निरंतर सुधार रही है। हालांकि, अप्रैल-जून 2021 में महामारी की दूसरी लहर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक गंभीर थी, पिछले वर्ष के राष्ट्रीय लॉकडाउन की तुलना में आर्थिक प्रभाव मौन था। अग्रिम अनुमान बताते हैं कि 2021-22 में जीडीपी 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक आर्थिक उत्पादन का स्तर 2019-20 के पूर्व-कोविड स्तर को पार कर जाएगा।

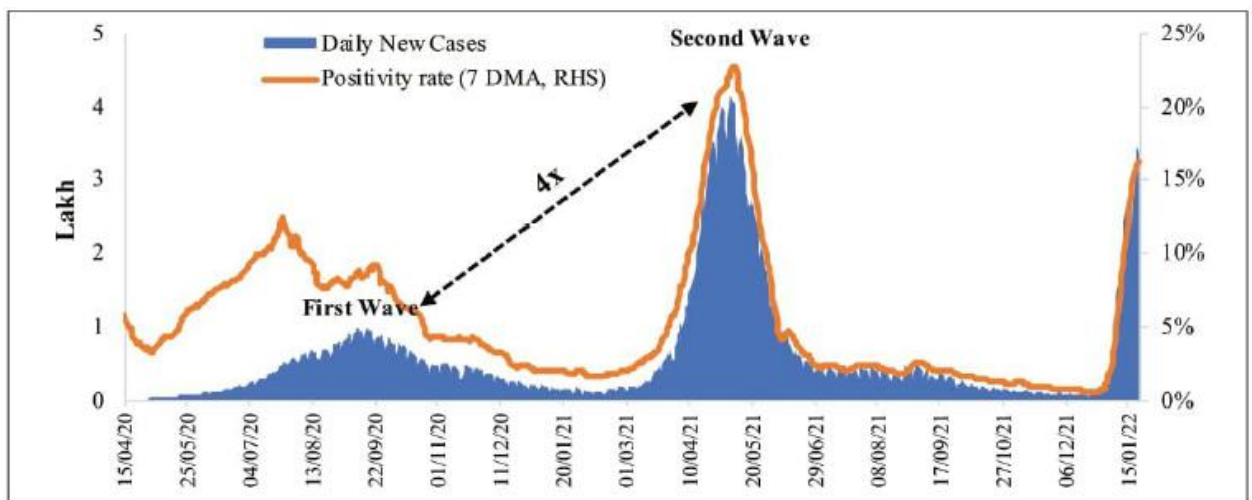


चित्र 1: सकल घरेलू उत्पादन (स्थिर मूल्य, आधार वर्ष: 2011-12)



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएसओ)

चित्र 2: कोविड-19 की लहरें



स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त डेटा नोट: डीएमए का मतलब डेली मूविंग एवरेज है

### क्षेत्र-वार चलन

कृषि क्षेत्र महामारी से संबंधित व्यवधानों से सबसे कम प्रभावित था (चित्र 3)। इसके यह पिछले दो वर्षों में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत के शीर्ष पर 2021-22 में 3.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है (तालिका 1)।

तालिका 1: स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)

क्षेत्र	2019-20 (पहला सं.अ.)	2020-21 (अ.अ.)	2021-22 (1 अग्रिम अ.)	2019-20 से बहाली की %
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	4.3	3.6	3.9	107.7
उद्योग	-1.2	-7.0	11.8	104.1
खनन और उत्खनन	-2.5	-8.5	14.3	104.6
उत्पादन	-2.4	-7.2	12.5	104.4
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	2.1	1.9	8.5	110.5
निर्माण	1.0	-8.6	10.7	101.2
सेवाएं	7.2	-8.4	8.2	99.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	6.4	-18.2	11.9	91.5
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं	7.3	-1.5	4.0	102.5
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.3	-4.6	10.7	105.6
<b>मूल कीमत पर जीवीए</b>	<b>4.1</b>	<b>-6.2</b>	<b>8.6</b>	<b>101.9</b>

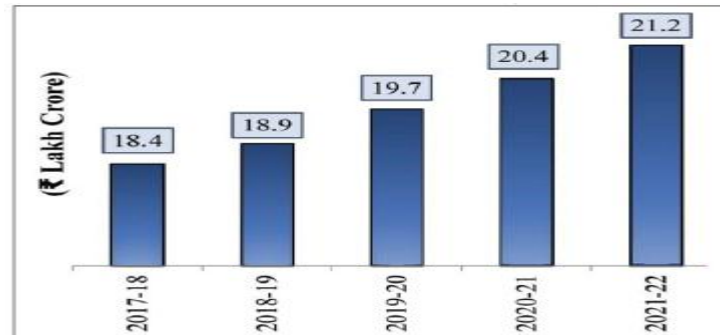
स्रोत: एनएसओ

नोट: सं.अ. - संशोधित अनुमान, अ.अ. - अर्न्तम अनुमान, अग्रिम अ. - अग्रिम अनुमान

खरीफ और रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र और गेहूं और चावल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। लंबी अवधि की रुझान के अनुरूप, 2021-22 के खरीफ चक्र में बोया गया क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में फिर से अधिक था (लेखन के समय रबी चक्र डेटा अधूरा था)। चालू वर्ष में, खरीफ सत्र का खाद्यान्न उत्पादन 150.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने का अनुमान है। केंद्रीय पूल के तहत खाद्यान्न की खरीद ने 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ अपनी बढ़ती रुझान को बनाए रखा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय के लिए अच्छा संकेत है। महत्वपूर्ण रूप से, इस क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन सरकारी नीतियां समर्थित था, जिससे महामारी संबंधी व्यवधानों के बावजूद समय पर बीज और उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। अच्छी मानसूनी बारिश से भी इसमें मदद मिली, जैसा कि जलाशय के स्तर में 10 साल के औसत से अधिक होना परिलक्षित होता है।

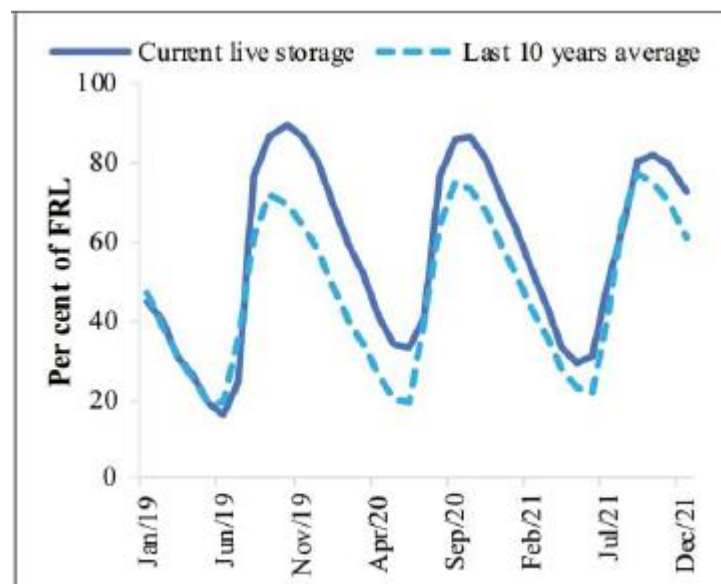


चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों



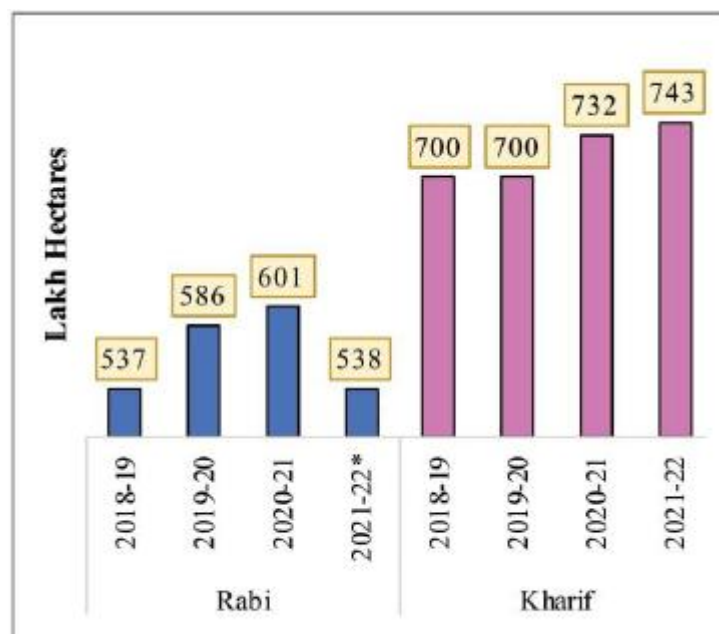
स्रोत: एनएसओ, केंद्रीय जल आयोग  
नोट: एफआरएल का अर्थ पूर्ण जलाशय स्तर है

चित्र 4: जलाशय का स्तर का वास्तविक जीवीए



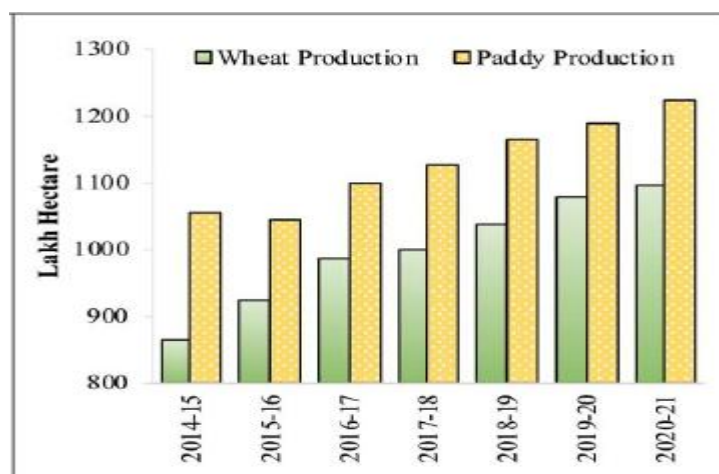
स्रोत: एनएसओ, केंद्रीय जल आयोग नोट: एफआरएल का अर्थ पूर्ण जलाशय स्तर है

चित्र 5: खाद्यान्न के तहत बोया गया क्षेत्र



स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; \*31 दिसंबर 2021 तक

चित्र 6: गेहूं और चावल का उत्पादन



स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; '31 दिसंबर 2021 तक

प्राथमिक क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन के विपरीत, औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 में पहले 7 प्रतिशत का संकुचन और फिर इस वित्तीय वर्ष में 11.8 प्रतिशत का विस्तार हुआ। विनिर्माण, निर्माण और खनन उप-क्षेत्र उसी रफ्तार से वृद्धि हुई, हालांकि उपयोगिता क्षेत्र में अधिक मंदी का अनुभव किया गया क्योंकि बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को राष्ट्रीय लॉकडाउन होने के बावजूद भी सही स्तर पर बनाए रखा गया था।

## निष्कर्ष

भारत का माल और सेवाओं दोनों का निर्यात 2021-22 में अब तक असाधारण रूप से मजबूत रहा है। वैश्विक आपूर्ति बाधाओं जैसे कि शिपिंग जहाजों का कम परिचालन, स्वेज नहर की रुकावट और चीन का बंदरगाह शहर आदि में कोविड-19 के प्रकोप जैसी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न व्यापार लागत में वृद्धि के बावजूद, व्यापारिक निर्यात 2021-22 में लगातार आठ महीनों के लिए 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा है।

समवर्ती रूप से, पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं, श्रव्य दृश्य और संबंधित सेवाओं, माल परिवहन सेवाओं, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं द्वारा संचालित शुद्ध सेवाओं के निर्यात में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

मांग के नजरिए से, भारत का कुल निर्यात 2021-22 में 16.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है जो महामारी से पहले के स्तर को पार कर जाएगा। घरेलू मांग में सुधार और आयातित कच्चे तेल और धातुओं की कीमत में निरंतर वृद्धि के साथ आयात में भी मजबूती आई।

2021-22 में आयात में 29.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो कि पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर गया है। 1.16 परिणामस्वरूप, भारत का निवल निर्यात 2021-22 की पहली छमाही में नकारात्मक हो गया है, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में अधिशेष की तुलना में चालू खाते में पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत का मामूली घाटा दर्ज किया गया है

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. JaganMohan, M.(2020). Travel and tourism industry in India, statistics and facts. <https://www.statista.com/topics/2076/travel-and-tourism-industry-in-india/>
2. Jan SaahasSurvey.(2020). Lockdown is only the beginning of misery for India's migrant labourers. Quartz.com. <https://qz.com/india/1833814/coronavirus-lockdown-hits-india-migrant-workers-pay-food-supply/>
3. KPMG.(2020). Corona virus: India's GDP growth may fall below 3% if lockdown extends, says KPMG report.
4. BusinessToday. <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus-india-gdp-growth-may-fall-below-3-if-lockdown-extends-says-kpmgreport/story/400135.html>
5. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/097206342093>
6. <https://thewire.in/economy/covid-19-india-economic-recovery>
7. <https://www.inventiva.co.in/stories/priyadharshini/how-is-the-indian-economy-affected-by-covid-19/>

8. <https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/blog/impact-of-covid-19-on-the-indian-economy/4241>
9. <https://government.economictimes.indiatimes.com/news/economy/opinion-impact-of-covid-19-on-the-indian-economy/75021731>
10. Garg, B., & Sahoo, P. (2020). Corona crash: Need global efforts to tackle global crisis (Policy Brief, No. 12). Institute of Economic Growth.
11. Gupta, M., & Minai, M. H. (2019). An empirical analysis of forecast performance of the GDP growth in India. *Global Business Review*, 20(2), 368–386.